जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 27 संख्याः 218 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 10 मार्च, 2023 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कम्बोडिया से चुराई गई शाही अंगकोर जूलरी का खजाना कंबोडिया को लौटा दिया गया है। अंगकोर के मध्यकालीन राजवंश की कुल 77 कलाकृतियाँ बीसवीं सदी के ख़मेर रूज काल और गृह युद्ध के दौरान देश से बाहर ले जाई गई थीं। पूर्वी एशिया में 9वीं से 14वीं सदी के बीच अंगकोर राजवंश महानतम ताकतों में से एक था। उनकी धर्मशासित राजधानी अंगकोरवाट, मध्यकालीन विश्व के सात अजूबों में से एक मानी जाती है और आज भी यह पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक कॉम्प्लैक्स है। कम्बोडिया के संस्कृति व कला मंत्रालय ने कहा कि, खजाने में कई ऐसे मुकुट भी हैं, जिन्हें राजाओं ने पहला था। सोने व अन्य कीमती धातुओं से बनी इन वस्तुओं में अंगकोर काल और उससे भी पहले के दौर की कलाकृतियाँ व आभूषण हैं, जिनमें मुकुट, हार, ब्रेसलैट, बैल्ट, झुमके और ताबीज़ प्रमुख हैं। सत्तर के दशक में जब कम्बोडिया गृह युद्ध और ख़मेर रूज के नरसंहार से त्रस्त था, उस समय यहां से हजारों कलाकृतियां लूटी गईं और थाईलैंड व हाँगकाँग के डीलर्स के जरिए यूरोप व अमेरिका के रईसों व म्यूज़ियमों को बेची गईं। गत वर्ष अमेरिकी नागरिकों व संस्थाओं ने स्वेच्छा से या कोर्ट के आदेश पर कई वस्तुएं लौटा दी थीं। कम्बोडिया के मंत्रालय ने बताया कि, 77 कलाकृतियाँ ब्रिटिश एंटीक्विटी डीलर डगलस लैचफोर्ड का परिवार ने लौटाई हैं। लैचफोर्ड का 2020 में अमेरिका में निधन हो गया, जहां उस पर कलाकृतियों की तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाया जाने वाला था। कलाकृतियों में दसवीं सदी के हिंदू देवता स्कंद की मयूर पर विराजमान अद्भुत मूर्ति भी शामिल है। इससे पहले वाले वर्ष में लैचफोर्ड ने कांसे की और पत्थर की 5 मूर्तियां कम्बोडिया को लौटा दी थीं। कम्बोडिया के संस्कृति मंत्री ने कहा, कलाकृतियों की वापसी को हम नेक कार्य मानते हैं, जो न केवल एक देश की संस्कृति में योगदान को दर्शाता है बल्कि कम्बोडिया के प्रति दोस्ताना रूख को भी दर्शाता है जो ख़मेर रूज के भारी नरसंहार की दुखांतिका से पीड़ित रहा है।

'मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान द्वारा की गई किसी भी छेड़छाड़ का "मिलिटरी" जवाब देगा'

अमेरिका की इन्टैलीजैंस एजेंसियों ने अमेरिका की कांग्रेस को प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट ने अपना यह आकलन पेश किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मार्च। अमेरिका अपनी इन्टैलीजेन्स कम्युनिटी की एक सूचना पर उच्च श्रेणी की चौकसी बरत रहा है। इस कम्युनिटी ने अमेरिका के सांसदों को सूचित किया है कि भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि इनके बीच अब तक का सबसे भीषण संघर्ष होने की आशंका है।

अमेरिकन इन्टैलीजेंस कम्युनिटी ने यह भी रेखांकित किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के अधीन भारत के द्वारा पाकिस्तान के किसी "वास्तविक या अनुभूत उकसावे के प्रति पहले की तुलना में सैन्य शक्ति का प्रयोग करने की अधिक संभावना है।

बुधवार को प्रस्तुत यह मूल्यांकन यू.एस. इन्टैलीजेंस कम्युनिटी के उउस वार्षिक चुनौती आकलन का भाग है, जिसे कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान डॉयरैक्टर ऑफ नैशनल इन्टैलीजेंस के ऑफिस द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन जहां अपनी-अपनी सीमा को लेकर द्विपक्षीय वार्ताओं और बॉर्डर पॉइन्ट्स का मुद्दा सुलझाने में संलग्न है, वहीं वर्ष 2020 में इन दोनों देशों के बीच हुई सदी की सबसे घातक झड़प के बाद इनके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।

- **रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, पाकिस्तान का पुराना इतिहास है कि, वह भारत विरोधी आतंकवादी ग्रुप्स को समर्थन व सहायता प्रदान करता है। कश्मीर में हिंसा, अशांति या आतंकवादी आक्रमण की कोई भी घटना हिन्दुस्तान की ओर से सैनिक (मिलिटरी) कार्यवाही शुरू करवा सकती है।**
- **दूसरी ओर अमेरिका व पाकिस्तान में आतंकवादी विरोधी को रोकने के लिये दो दिन तक वार्ता चली। अमेरिका का अभी भी विश्वास है, दोनों देशों में आतंकवाद को रोकने के बारे में मतैक्यता है तथा यह मतैक्यता इस क्षेत्र में शांति बनाये रखने में अहम् भूमिका रखती है।**

इनमें कहा गया कि विवादित सीमा पर भारत और चीन का विस्तारित सैन्य रूख, इन दोनों परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के बीच सैनय संघर्ष का ऐसा जोखिम बढ़ाता है, जिसमें अमेरिका के नागरिकों और उसके हितों को प्रत्यक्ष चुनौती मिल सकती है, अतः इसमें अमेरिका के हस्तक्षेप करने की जरूरत है। दोनों के बीच पहले हुए गतिरोधों ने दर्शा दिया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एल.ए.सी.) पर हल्के-स्तर पर निरन्तर बने हुए टकराव के तेजी से विकराल रूप लेने की आशंका है।

पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में हुई सैन्य झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंध एक तरह से बिगड़ चुके हैं।

भारत यह बात कहता आया है कि चीन से लगती सीमा पर जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उसके साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच का संकट विशेष रूप से चिन्तित करने वाला है क्योंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जॉच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

मुसलमानों को लुभाने के लिए भाजपा ने नया नारा दिया

इस "एक देश, एक डी.एन.ए." के नारे के तहत गतिविधि वैस्टर्न यू.पी. से आरंभ की जायेगी

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मार्च। अगले वर्ष के संसदीय चुनावों से पहले मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये, भाजपा पुरस्कार और दंड की नीति अपनाती प्रतीत हो रही है।

अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लक्ष्य करके बनाये गये एक सम्पर्क-कार्यक्रम के अन्तर्गत, भगवा पार्टी एक "स्नेह मिलन" अभियान चलायेगी, जिसकी टैगलाइन होगी- "एक देश, एक डी.एन.ए.।" इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। पार्टी सूत्रों ने कहा, "मई में ईद के बाद शुरु होने वाले इस अभियान से प्रत्येक गाँव के मुखिया और प्रधान जोड़े जायेंगे।"

भाजपा नेता अपने चुनाव-प्रचार के भाषणों में प्रायः मुस्लिम समुदाय को निशान्त बनाते हुये सुनाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्ष अपने प्रचार के दौरान दिये गये भाषणों "80:20 के अनुपात" का जिक्र किया था। अपने दूसरे कार्यकाल के शुरु होते ही, आदित्यनाथ ने "बुलडोज़र राजनीति" भी अपनाई थी, जिसमें अधिकांशतः

- **वैस्टर्न यू.पी. में, विशेषकर हिन्दू व मुसलमान के बीच कई पुरानी पारम्परिक व सांस्कृतिक समानताएं हैं। यहां तक की "सरनेम" भी कॉमन हैं, जैसे त्यागी, चौहान, तोमर, राव आदि।**
- **भाजपा रणनीतिकार अब यह महसूस कर रहे हैं कि, मुसलमान विरोधी सोच उन्हें यहां तक तो ले आया, पर, अब आगे बढ़ने के लिये मुसलमानों को साथ लेना होगा।**
- **अब तक भाजपा हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिये काफी हद तक मुसलमान विरोधी रवैया व सोच ही रखती थी। यू.पी. के मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले 80:20 का नारा दिया था तथा जे.सी.बी. अभियान चलाया था "अतिक्रमण" तोड़ने के लिये।**
- **अब रणनीति में कुछ परिवर्तन कर, मुसलमानों को रिझाने के लिये, पसमन्दा मुसलमानों के सम्मेलन, सूफी संवाद महा अभियान, आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अडानी मामले में "लाई डिटैक्टर टैस्ट" करवाएं मोदी'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मार्च। एनफोर्समैन्ट डायरेक्ट्रेट (ई.डी) द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ करने के लिये के. कविता को सम्मन भेजे जाने के एक दिन बाद ही, भारत राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.) ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला शुरु कर दिया है। के. कविता बी.आर.एस. प्रमुख तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की पुत्री हैं।

- **तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पुत्री को दिल्ली के "लिकर कांड" में सम्मन दिए जाने से भड़की, भारत राष्ट्र समिति ने मोदी पर अडानी को लेकर हमला बोला।**

जैसे ही, कविता गुरुवार को पूछताछ के सिलसिले में तथा मोदी सरकार के खिलाफ भूख-हड़ताल करने के लिये पहुँची, उनके भाई के.टी. रामाराव ने दृढ़ स्वर में कहा कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री का "प्रॉक्सी" है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खड़गे ने क्यों कहा, वे खुश और संतुष्ट हैं अशोक गहलोत सरकार से

खड़गे के इस ट्वीट से राजस्थान के कांग्रेसी न केवल हैरान बल्कि स्तब्ध भी हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सशक्त मैसेज दिया है कि वे अशोक गहलोत सरकार से खुश एवं संतुष्ट हैं।

एक ट्वीट, जिसने राजस्थान को चकित भी कर दिया और स्तब्ध भी, में उन्होंने गहलोत की इंदिरा थाली योजना का समर्थन किया और तारीफ की तथा कहा कि इससे 9.3 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है।

यह योजना काफी समय से चल रही है, इसलिए सवाल यह उठता है कि खड़गे ने गहलोत सरकार की इतनी तारीफ क्यों की और क्यों यह संकेत दिया कि गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसे समय में जब वरिष्ठ नेता सचिन पायलट नेतृत्व परिवर्तन के लिए मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में नेतृत्व बदला जाए, तब खड़गे ने यह ट्वीट क्यों किया है।

सवाल पूछा जा रहा है, क्या यह उचित है कि खड़गे राजस्थान सरकार पर एक तरफा राय बनाएं व दूसरे गुट के नजरिए की पूरी तरह से अनदेखी कर दें। सवाल फिर से यही उठता है कि खड़गे गहलोत को पूरी तरह से समर्थन देने जा रहे हैं और उन्हें राजस्थान, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, में पार्टी का सबसे सशक्त दांव मानते हैं तो सचिन पायलट

- **सवाल यह उठता है अगर नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनकी सरकार से खुश और संतुष्ट हैं तो सचिन पायलट से किए गए वायदों का क्या होगा।**
- **मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान सरकार की 8 रू. की इंदिरा थाली योजना के लिए गहलोत सरकार की प्रशंसा में ट्वीट किया, जिससे राजनैतिक हलकों में बहस छिड़ गई है।**
- **सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार खड़गे के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संभवतया वह हस्तक्षेप करने का इच्छुक भी नहीं लगता है।**
- **पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर सोनिया व राहुल में गहलोत को हटाने की हिम्मत होती तो वे अब तक ऐसा कर चुके होते।**
- **बात स्पष्ट है राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका ने सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के वायदे तो कई बार किए पर आज तक इस पर अमल नहीं किया।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोबाइल फोन क्यों तोड़े, ई.डी. ने सिसोदिया से पूछा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय तिहाड़ जेल में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (51) से दूसरी बार पूछताछ कर रहा है। यह पूछताछ शराब नीति में कथित अनियमितताओं के विषय में उनके द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों तथा उनके द्वारा अपनाई गई टाइमलाइन को लेकर की जा रही है। सिसोदिया से उनके

- **दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट ने तिहाड़ जेल में दूसरी बार पूछताछ की। ई.डी. का कहना है कि, सिसोदिया मोबाइल फोन नष्ट किए जाने का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जब तक एडवोकेट प्रोटैक्शन बिल पेश नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगी, वकीलों की चेतावनी

वकीलों की हड़ताल का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया, 21 मार्च को होगी सुनवाई

जोधपुर/जयपुर, 9 मार्च (कासं)। राजस्थान में चल रही वकीलों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीज़नल बैंच ने सुनवाई की।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व जस्टिस विजय विश्नोई की बैंच ने राज्य भर के सभी बार संघ को नोटिस जारी किया। साथ ही, इन संघ के अध्यक्ष व सचिवों से 21 मार्च तक शपथ पत्र मांगा है।

नोटिस में पूछा गया है कि उन्होंने किस कारणवश हड़ताल की है और क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब इस मामले में 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। प्रदेशभर के वकीलों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की। वकीलों की हड़ताल के चलते नोटेरी से लेकर सारे न्यायिक काम ठप पड़े हैं।

गौरतलब है कि 18 फरवरी को जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में वकील जुगराज चौहान की बीच रास्ते चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जोधपुर के वकील हड़ताल पर चले गए और वे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग करने लगे।

धीरे-धीरे इस एक्ट के समर्थन में प्रदेश के अन्य वकील भी उतर गए। प्रदेशभर के एडवोकेट हड़ताल पर हैं। वकीलों का कहना है कि उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। इधर, वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट के सारे काम ठप पड़े हैं। लगातार 21 दिनों से न्यायिक कार्य प्रभावित होने के चलते हाईकोर्ट ने 2 मार्च को संज्ञान लिया था। इसी दिन पहली सुनवाई थी। इस दौरान समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि 13 मार्च को राजस्थान के सभी एडवोकेट विधानसभा का घेराव करेंगे। लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि भंसाली ने बताया कि राजस्थान में 1 लाख 10 हजार वकील हड़ताल पर हैं। प्रदेश में मुख्य रूप से 5 बार एसोसिएशन हैं, तीन जयपुर में व दो जोधपुर में, प्रदेशभर में 300 बार एसोसिएशन हैं। अभी हड़ताल के चलते कोर्ट में केस की सुनवाई, जमानत, स्टे पिटीशन दायर करने के काम प्रभावित हो रहे हैं। वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति और वकीलों के बीच सहमति बनी है। गुरुवार को वकीलों के साथ मंत्रिमंडलीय उप समिति ने चर्चा की।

- **सी.जे. श्रीवास्तव की बैंच ने बार एसोसिएशन व वकीलों को नोटिस जारी कर पूछा कि, उन्होंने हड़ताल क्यों की है, क्यों ना उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।**
- **इधर गुरूवार को वकीलों व मंत्रिमंडल उपसमिति के बीच सहमति बनी है, एडवोकेट प्रोटैक्शन बिल 15 मार्च को विधानसभा में पेश हो सकता है।**

विधि व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लालचंद कटारिया, रामलाल जाट व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुभाष गर्ग वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी व प्रतापसिंह खाचरियावास फिजिकल तौर पर शामिल हुए। वहीं विधि विभाग के प्रमुख विधि सचिव ज्ञान प्रकाश गुप्ता, विधि सचिव अनुपमा बिजलानी व एजी के प्रतिनिधि के तौर पर एएजी डॉ. विभूति भूषण शर्मा भी शामिल हुए, जबकि वकीलों की ओर से बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा, महासचिव मनोज कुमार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'इंसाफ विपक्षी दलों का कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मार्च। जाने-माने सीनियर एडवोकेट एवं निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि उनका नवगठित संस्थान "इंसाफ" गैर-चुनावी है, किन्तु यह एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है और भारत में वर्ष 2014

- **वरिष्ठ वकील व स्वतंत्र सांसद कपिल सिब्बल ने गत शनिवार को स्थापित "इंसाफ" मंच के बारे में बताते हुए यह भी कहा कि, यह राजनैतिक प्लेटफॉर्म है, पर चुनाव नहीं लड़ेगा।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)